

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 92/2013/उदयपुर

मैसर्स पॉयरोटेक वर्कस्पेस सॉल्यूशन्स प्रा.लि., उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के.एल.चंचावत,  
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :21.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या-186/वैट/2011-2012 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शारित रु.75,000/- व कर रु. 35,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 25.09.2011 को वाहन संख्या आर.जे. 27-1जी-1006 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8, खजूरी जिला-डूंगरपुर पर वास्ते जांच रोका गया। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन में लदे माल "Modular Storage facility for kitchen Inclusive of Necessary Hardware, fixing Accessory Finishing" जो कि स्टॉक ट्रांसफर पर गुजरात के लिये परिवहनीत किया जा रहा था, के संबंध में दस्तावेज चाहने पर, वाहन चालक ने संबंधित दस्तोवज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, माल संबंधी दस्तावेजों में अधिसूचित वस्तुओं को परिवहनीत करने के बावजूद, घोषणा प्ररूप वैट-49 संलग्न नहीं पाये जाने

लगातार.....2

के कारण, वाहन चालक के बयान दर्ज किये। जिनमें वाहन चालक ने घोषणा प्ररूप वैट-49 नहीं होना प्रकट किया। फलस्वरूप, प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-49, संलग्न नहीं होने के कारण, उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत अभियोग दर्ज कर, प्रकरण को सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने बनाये गये अभियोग के आधार पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से श्री सचिन उदोले, व्यवसाय प्रबंधक उपस्थित हुये एवम् मय जवाब के घोषणा प्ररूप वैट-49 क्रमांक 5272326 प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जांच घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर, आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इसे प्रस्तुत अपील के जरिये चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि जांच के समय हालांकि घोषणा प्ररूप वैट-49 प्रस्तुत नहीं किया था, परन्तु उक्त भूलवश था। उन्होंने तर्क दिया कि व्यवहारी ने घोषणा पत्र वैट 49 हेतु कार्यालय में दिनांक 23.09.2011 को आवेदन किया था परन्तु अवकाश आदि की वजह से उनको घोषणा पत्र दिनांक 26.09.2011 को प्राप्त हुआ परन्तु इस दौरान माल भेजने की आवश्यकता के मध्यनजर दिनांक 24.09.2011 को ही माल प्रेषित कर दिया इस वजह से घोषणा पत्र दस्तावेजों के साथ नहीं भेजा जा सका। परन्तु नोटिस के साथ प्रस्तुत कर दिया गया। अतः प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप वैट-49 को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित करना पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना विधिअनुकूल नहीं है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी. सी. 611 मै0 डी.पी.मेटल्स, को प्रोद्धरित किया गया। अतः ऐसी स्थिति में, आरोपित



शास्ति विधिक है। उक्त विधिक व तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, अपीलीय आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने पारित शास्ति आदेश का समर्थन कर, कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा घोषणा प्ररूप वैट-49 प्रत्यर्थी के समक्ष, जो प्रस्तुत किया गया है, वह बाद की सोची गयी युक्ति है क्योंकि प्रारंभ में दस्तावेज चाहने पर माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-49 प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अग्रिम तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित विधि का सहारा लिया जाना न्यायसम्मत नहीं है। जैसाकि माल के परिवहन के वक्त माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप वैट-49 संलग्न नहीं था, न ही इसके होने के संबंध में वाहन चालक ने अपने बयानों में कोई कथन ही किया था, न ही इसे प्रस्तुत करने में कोई "भूल" हुयी थी। तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि वक्त जांच बिल, बिल्टी व घोषणा प्ररूप वैट-47/49 प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। अतः ऐसी स्थिति में, माननीय शीर्ष न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत गुलजग इण्डस्ट्रीज़ 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत एवम् उचित होना प्रकट कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि वक्त जांच प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष राजस्थान मूल्य परिवर्धित नियम .....नियम 54(1)(i) के तहत विहित वांछित घोषणा प्ररूप वैट-49 प्रस्तुत नहीं किया गया था, न ही प्रारंभ में माल प्रभारी/वाहन चालक द्वारा जांच के समय इसे "भूलवश" माल संबंधी दस्तावेजों में संलग्न नहीं करना ही प्रकट किया गया था। जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 के मामले में विधि प्रतिपादित की गयी है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में "भूलवश" घोषणा प्ररूप वैट-47 की अप्रस्तुति, शास्ति से बचने का प्रयास करना है। व्यवहारी ने वाहन जांच के पश्चात कार्यालय से वैट 49 जारी करवाया है अतः "भूलवश" वैट 49 प्रस्तुत नहीं करने का कथन अप्रासंगिक है।


✓

लगातार.....4

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने निर्णय आशियाना इस्पात लि० (2010) 01 आर.जी.एस.टी.आर.-डी-014 (एस.सी.)के प्रकरण में भी जांच के समय वैद्य घोषणा प्ररूप नहीं होने को मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 के निर्णयानुसार विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होना अवधारित कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील खारिज की है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान न्यायालय की एकलपीठ ने स.वा.क.अ., जयपुर बनाम् पी. एल.मोटर्स लि., जयपुर के प्रकरण WLC(Raj.)2011(1)371 में पैरा-14 में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की गयी है:"....**Apart from above, it is also relevant to mention that admittedly Declaration Form ST18-A was not accompanied with the goods when the truck in dispute was checked. Hon'ble Apex Court in Guljag Industries Vs Commercial Taxes Officer, reported in (2007) 7 SCC 269 has already held that provisions of Section 78(2) of the Act 1994 are mandatory in nature. Since declaration Form ST 18-A was required to be accompanied with the goods at the time of checking and it was not there in the present case, therefore, provisions of Section 78(2) were violaltd and penalty was liable to be imposed under section 78(5) of the Act of 1994.**" अतः उक्त प्रतिपादित विधिक स्थिति के प्रकाश में, यह अवधारित किया जाता है कि माल संचलन के दौरान, माल संबंधी दस्तावेजों में वैद्य घोषणा प्ररूप का नहीं होना, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों की अवहेलना है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, कर चोरी के आशय को प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं माना गया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को सम्मान व्यक्त कर, नियम 54 के विधिक प्रावधानों की अवहेलना होने व इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों 18 टैक्स अपडेट 321 व (2010) 01 आर.जी.एस.टी.आर.-डी-014 (एस.सी.) व **WLC (Raj.) 2011 (1) 371** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश शास्ति के बिन्दु पर विधिसम्मत एवम् उचित होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।

  
21.8.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य